SHRI JAGANATH RAO : The Indian Copper Corporation at Ghatsila is producing only 9,000 tonnes, not 16,000 tonnes as the hon. member said. The production, is is hoped, will be stepped up to 16,000 tonnes by 1973-74. About the pendency of the applications for licence, I am not in a position to say anything. We want to do it in the public sector.

SHRI N. K. SOMANI : During the last one year, Operation Hard Rock has made it possible to find out extensive and rich deposits of non-ferrous metals, including copper, in various States like Bihar, Rajasthan, Andhra Pradesh, etc. May I know from the Government of India what specific programmes are they going to undertake as a result of this valuable findings and secondly, since the Government is considering to Indianise the Operation Hard Rock version by equipping their own aircraft, what is the progress achieved in this particular phase of investigation ?

SHRI JAGANATH RAO : The airborne geophysical surveys have enabled us to discover valuable deposits of metals all over the country. What are called anomalies have to be worked and they have to be mapped in the maps. We are anxious to see that the deposits that have been discovered are worked out.

SHRI N. K. SOMANI : What about the second phase, Indianisation of the operation ?

SHRI JAGANATH RAO : That comes later, not at this stage.

श्री सोताराम केसरी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की स्थापना से लेकर आज तक उसमें सालाना क्या आपने यह ब्यौरा निकाला है कि चोरियों के कारण और अनियमितताओं के कारण कितनी आप को हानि हुई है ? यदि निकाला है तो उसका कोई आपके पास तखमीना है ?

SHRI JAGANATH RAO : That comes in the next Question.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां

*516. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सहकारी गृह निर्माण के लिये भूमि आवंटित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहकारी गृह-निर्माण समितियों तथा केन्द्रीय सहकारी कर्मचारियों की, जिन्हें भूमि आवंटित की जायेगी, संख्या कितनी हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक समिति को कितनी भूमि आवंटित की जायेगी तथा निर्णय के अनुसार ऐसी भूमि कहां-कहां आवंटित की जायेगी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन ने इन सहकारी गृह-निर्माण समितियों से भूमि का मूल्य पहले ही वसूल कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक कितनी राशि वसूल की गई है; और

(च) इन समितियों को मकानों के निर्माण के लिये भूमि कब तक दी जायेगी ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : (a) to (f). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—366/69].

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : स्टेटमेंट में 23 बिल्डिंग सोसाइटीज के बारे में तालिका दी गई है जिसमें 10 कोआपरेटिव सोसाइटीज को लैंड के एलाटमेंट के बारे में कुछ किया

गया। बाकी 13 के बारे में हालांकि करीब-करीब 2 करोड़ रुपया वसूल कर लिया गया है प्रीमियम के रूप में जैसा कि इसमें दिखलाया गया हैं लेकिन अभी तक लैंड का डीमार्केशन तक नहीं हुआ है और रीजन यह दिया गया है कि स्टे आर्डर कर दिया गया है इसलिये टाइम लगेगा। मैं यह पूछना चाहूंगा कि कितना टाइम लगेगा और अगर 5 या 10 साल का समय लगे तो क्या और किसी जगह यह एलाटमेंट जल्दी करने की कोशिश करेंगे ?

दूसरी चीज, एक तारा कोआपरेटिव सोसाइटी भी है। उसके बारे में क्या चल रहा है ? क्या डीटेल्स हैं ? एलाटमेंट होगा या नहीं होगा ? प्रीमियम आ गया या नहीं, इसके बारे में कुछ बताएंगे ?

श्री के० के० शाह : मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फरवरी 1968 में आखीरी जजमेंट आ गया है। इसलिये अभी तो कोशिश जो अनएथोराइज्ड आक्यूपेशन है उसको निकालने की हो रही है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।

तारा कोआपरेटिव सोसाइटी जो मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट की है उसके लिए मैं दो-तीन महीने में उसकी कार्यवाही कर दूंगा।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं सरकार से यह तथ्य जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटीज को भूमि आप आज इस कारण से नहीं दे रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट करने पर आपका मतभेद है ? सरकार यह चाहती है कि भूमि को डेवलप कर के दिया जाय और धन कमाया जाय। इन्हीं कारणों से वह देरी लगा रही है जबकि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जो डेवलपमेंट करने के लिये स्वयं तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली नगर निगम ने इस स्कीम का समर्थन किया है कि गवर्नमेंट भूमि सोसाइटीज को दे दे और वह अपने आप डेवलपमेंट करके कालोनीज बसा लेंगे ? क्या गवर्नमेंट इस बात के लिये तैयार है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को अनडेवलप्ड भूमि दे दे और वह डेवलपमेंट करके अपने आप कालोनीज बसा लें ?

श्री के० के० शाह : 284 सोसाइटीज सारी बनीं इनमें से 210 ने उस जमीन के लिये अर्जी दी। अर्जी के बाद आफर किया। आफर करने के बाद 147 ने पैसा जमा किया। 147 में से जो लोग पूरा पैसा जमा नहीं कर सके हैं उनको हम डेवलपमेंट करके इंडिविडुअल प्लाट देते हैं। जो पूरा पैसा जमा करते हैं वह खुद डेवलपमेंट कर दें, हमारा कोई झगड़ा उन के साथ नहीं है।

REHABILITATION WORK IN NORTH BENGAL

*517. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have provided a considerable amount for the work of rehabilitation in flood-affected districts of North-Bengal ;

(b) if so, the progress made in rehabilitation ; and

(c) the precautions taken to check the misuse of funds ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) Yes Sir.

(b) A statement based on the information received from the State Government is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—567/69]

(c) It is for the State Government to ensure that the funds allocated for relief and rehabilitation measure are praperly utilised. As far as the Government of India are concerned, accounts of Central assistance will be finally settled only on the basis of the figures of expenditure certified by the Accountant General.

SHRI M. L. SONDHI : The hon. Finance Minister is aware that many of these certified accounts do not give a true picture unless vigilance is exercised by the Central Government. May I know from the hon. Minister